



ਛੁਟ੍ਕਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

लरवनऊ, कानपुर, कन्जीज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोणडा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

शुक्रवार, 01 अप्रैल 2022 सिद्धार्थनगर संस्करण

www.budhakasandesh.com

वर्ष: 09 अंक: 102 पृष्ठ 8 आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

लखनऊ सुचीबद्ध कोड—SDR-DLY-6849, डी.ए.वी.पी.कोड—133569 | सम्पादक: राजेश शर्मा | उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

सबसे शतिशाली लोगों की लिस्ट में टॉप पर पीएम मोदी, योगी के ग्राफ में बड़ा इजाफा, जानिए राहुल का क्या है हाल?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति और वैश्वक कूटनीति का एक ऐसा नाम है जिसका डंका दुनियाभर की चौपालों पर बज रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है और वो देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा इस सूची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी



हुए हैं। योगी के ग्राफ में बड़ा इजाफा : पीएम मोदी के बाद इस सूची में दूसरे नंबर पर अमित शाह, तीसरे नंबर पर मोहन भागवत, चौथे पर जेपी नड्डा, पांचवें पर मुकेश अंबानी और छठे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और इसके साथ पावर लिस्ट 2022 को पक्का किया गया है। पिछले साल के 13वें नंबर से योगी आदित्यनाथ छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा इस सूची में सातवें नंबर पर गौतम अडानी, आठवें पर अजित डोभाल, नौवें पर केजरीवाल, दसवें पर निर्मला सीतारमण हैं। इस लिस्ट में राहुल गांधी 51वें नंबर पर हैं।

ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की घटना के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। पड़ताल के लिए पुलिस की छह टीमें छापेमारी में लगी हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 30 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित हमले और तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आयी थी। सौरभ भारद्वाज की याचिका में हमले और इसके अपराधियों के संबंध में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध आपराधिक

के चारों ओर सुरक्षा अवरोध टूट गया। दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण में, केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को बढ़ावा देने के लिए भाजपा पर निशाना साधा था। जिसके बाद उनका लोगों ने काफी विरोध किया था। केजरीवाल की जान को खतरा?: सीएम आवास पर हमले के बाद, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश करने का आरोप लगाया। आप के एक अन्य नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि भाजपा सीएम अरविंद केजरीवाल की छत्याकरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है केजरीवाल माफी मांगें: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ताड़काड़ी की। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने बयान के लिए कार्यकर्ताओं के एक समूह का नेतृत्व केजरीवाल के आवास के सामने किया, जहां उन्होंने कथित तौर पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा करार दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उपहास के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा ने केजरीवाल से बिना शर्त माफी की मांग की। युवा मोर्चा का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वे माफी नहीं मांग लेते। राम मंदिर का मजाक बनाना, हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उठाना, बटला हाउस पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना आम आदमी पार्टी की नीति रही है।

सीएम सरमा ने दिए संकेत,
छिन सकता है मुसलमानों
से अल्पसंख्यक का दर्जा

ਲਾਹੌਰ ਗਡੀ ਖਰੀਦਨੇ ਪਰ ਰੋਕ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਣਾ

**जानें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे
टारगेट दे मंत्रियों को काम पर लगाया**

नज़ | उत्तर प्रदेश में 5 100 दिनों के कामकाज का अर्जेंडा नहीं करने की कायम कामकाज के बारे में

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को जिलेवार परिभाषित करने की वकालत करती है। सरमा ने कहा कि राज्य दिल्ली भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका के आधार पर चल रहे सुप्रीम कोर्ट के मामले में पक्षकार बनने की कोशिश करेगा। इस मामले में केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि राज्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर विचार कर सकते हैं यदि समुदाय उनके अधिकार क्षेत्र में बहुसंख्यक नहीं है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार असम की अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी 33: से थोड़ा अधिक है। लेकिन, राज्य के भीतर नौ जिले हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। उन्होंने कहा, पिछले 75 वर्षों से एक अवधारणा है कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है, लेकिन अब यह अवधारणा चुनौती में आ गई है और यह बताया गया है कि हिंदुओं को भी उनके धर्म के लिए खतरे की धारणा के आधार पर एक विशेष राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए असम के संदर्भ में, दक्षिण सलमारा जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। राज्य सरकार का मानना छहौं कि अल्पसंख्यक की परिभाषा जिलेवार बदली जानी चाहिए। हम अश्विनी उपाध्याय मामले में असम सरकार को पक्षकार बनाने का प्रयास करेंगे और अल्पसंख्यकों को जिलेवार परिभाषित करने पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सरमा ने कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर चर्चा की है। लेकिन, राज्य के पार्टी बनने की कोई गुजाइश है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करता है। इस सरमा ने कहा कि केंद्र सरकार भी अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक, शैक्षिक, लिंग और अन्य सामाजिक मानकों पर विचार करते हुए जिला और ब्लॉक-वार परिभाषित करने के पक्ष में है। भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में, बराक घाटी और धुबरी जिले में बंगाली अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन वे डिल्गढ़ और ऊपरी असम क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हैं।

A photograph of Jagadguru Kripalu Swami Prabhupada, an elderly man with a shaved head, wearing an orange robe, sitting and speaking. He is gesturing with his hands as he talks. The background is dark.

का आर मात्रया का दिए गए निर्देशों के तहत उन्हें पुराना स्टाफ नहीं रखने और अपनी मर्जी से निजी स्टाफ रखने से बचने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार को कर्तव्य बर्दाश्त नहीं करने और पारदर्शिता बरकरार रखने की अपनी पिछली सरकार की छवि को बनाए रखने के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। 100 दिन का मास्टर प्लान बनाकर सीएम के सामने करना होगा पेशः इनमें मंत्रियों को 100 दिन के कामों का लक्ष्य तय करने वाला अजेंडा थामाया गया है। इसके तहत सभी मंत्रियों को अपने विभाग के कामकाज की 100 दिन में समीक्षा कर आगे की कार्ययोजना का मास्टर प्लान बनाना होगा।

ना कांग्रेस नियरता है। इसा बाबू नव्य प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जी-23 के साथियों की मांगों को मान लिया गया है और 3 महीने में चुनाव होंगे। 3 महीने में होंगे संगठनात्मक चुनावः समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जी23 के लोग मेरे बहुत करीबी हैं, वे सालों से मेरे मित्र और सहयोगी रहे हैं। उनकी ऐसी कोई भी मांग नहीं थी, जो पूरी नहीं हो सकती थी। उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। जी-23 के लोग चुनाव चाहते थे और 3 महीने में चुनाव होंगे, सबकुछ आप लोगों के सामने होगा। कौन हैं जी-23 के नेता?: जी-23 कोई अलग समूह नहीं है बल्कि यह लोग कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं। दरअसल, गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के 23 नेताओं ने नेतृत्व के प्रति असंतोष जताते हुए पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। जिसके बाद इन्हें जी-23 के नाम से पुकारा जाने लगा। गुलाम नबी आजाद जी-23 के अगुआ बनकर उभरे थे। जी-23 नेताओं में गुलाम नबी आजाद के अलावा कपिल सिंहल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजेंद्र कौर भट्टल शामिल हैं। हालांकि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश! भाजपा का होगा अपना मख्यमंत्री, बिहार की सियासत में अटकलों का दौर

हिन्दी दैनिक **बुद्ध का संदेश** समाचार पत्र

**मैं सत्कारी विज्ञापन,
निविदा, अदालती नोटिस,
सम्मान, सूचना, टैण्डर प्रकाशन
के लिए आज ही सम्पर्क करें।**

सभी जनपदों से आवश्यकता है पत्रकारों की

सम्पादक:- दैनिक बुद्ध का संदेश



भले ही पांच राज्यों में विधि-नसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इन चुनावों की ललचल सबसे ज्यादा थी। लेकिन बिहार की राजनीति में कई नवायासों का दौर शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि बीबीबी नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनेंगे और राज्य में राजपा का अपना मुख्यमंत्री बनेगा। इस चर्चा के बीच नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। कुछ ऐसा बयान दे दिया जेसके बाद इन दावों को और जबूती मिल रही है। दरअसल, नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा जाने की छाँ जताई। उन्होंने कहा कि गोकर्ण सभा, विधानसभा और विधि-न परिषद का वह सदस्य हो

चुके हैं। लेकिन अभी तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बने हैं।

इसी के बाद अब यह कथास लगाने शुरू हो गए हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे कर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे? कथास इस बात को लेकर भी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ऐसे में वह राज्यसभा के भी अधिकारी होंगे। 16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के इस बयान से इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि वह अब एक नई भूमिका के इच्छुक हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए

भाजपा का प्लान है। भाजपा का प्लान यह है कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाते हैं, ऐसे में राज्य में वह अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में 74 सीटें जीतने के बावजूद भी भाजपा ने 43 सीटों पर जीत हासिल करने वाली जदयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया। हालांकि अब वीआईपी पार्टी के भी तीन विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उसकी संख्या 77 हो गई है और वह बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

कौन बनेगा सीएम

जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के दिल्ली की राजनीति में जाने के साथ ही भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी। जबकि जदयू के कोटे से दो उपमुख्यमंत्री रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा दलित या ओबीसी चेहरे को बिहार में आगे कर सकती है ताकि जातियों का समीकरण बना रहे। वर्तमान में देखें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की रेस में भाजपा के सप्राट चौधरी और शाहनवाज हुसैन का भी नाम सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम की रेस में जदयू कोटे से मुंगेर के सांसद और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का नाम है। इसके अलावा बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद ही खास विजय कुमार चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार भी डिप्टी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं।

सम्पादकीय

हाई कोर्ट ने कहा कि संसद

कानून में मीजूद

असमानताओं को दूर करना चाहिए। यानी बात धूम-फिर कर संसद के दायरे में पहुंचती है। बहरहाल, हाई कोर्ट ने कहा- सदियों पुरानी सोच है कि पति अपनी पत्नियों के शासक होते हैं। वे उनके शरीर, उनके मन और आत्मा पर राज करते हैं। इस सोच के मिटा दिया जाना चाहिए...

Digitized by srujanika@gmail.com

व्यवस्था अगर ऐसी है, जिसके लिए कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है, तो न्यायालय की व्यवस्था तब तक एक राय ही रहती है, जब तक विधायिका उसके मुताबिक कानून निर्मित ना कर दे। इसका अपवाद सिर्फ तब होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला संविधान के अनुच्छेद 140 को लागू करते हुए दिया हो। आम समझ यह है कि हाई कोर्ट चूंकि संवैधानिक अदालत है, इसलिए उसका फैसला सारे देश में तब तक लागू होता है, जब तक कोई हाई कोर्ट उससे अलग व्यवस्था ना दे दे। जब उच्च न्यायालयों की व्यवस्थाएं परस्पर विरोधी हो जाएं, तो फिर अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है।



बहरहाल, व्यवस्था अगर ऐसी है, जिसके लिए कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है, तो फिर न्यायालय की व्यवस्थाएँ तब तक आधिका न्यायालय की भावना के मुताबिक कानून निर्मित ना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला संविधान के अनुच्छेद इसीलिए अगर इस सिस्टम को ध्यान में रखें, तो वैवाहिक व

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले एक सीमित महत्व का निर्णय ही समझा जाएगा। वर्तमान सरकार

की तरफ से यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि वह उस राय से सहमत नहीं है, जैसी हाई कोर्ट ने जताई है। तो इस बारे में कोई कानूनी प्रावधान होगा, इसकी उम्मीद कम ही है। बहरहाल, यह जरूर है कि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां कीं, उससे इस मुद्दे पर जारी बहस आगे बढ़ी है। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बैच ने कहा कि एक व्यक्ति केवल इसलिए दुष्कर्म के मुकदमे से बच नहीं सकता, क्योंकि पीड़िता उसकी बीवी है। बैच ने कहा यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। हाई कोर्ट की बैच ने बलात्कार के मामले को खारिज करने की पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। उसने बलात्कार के आरोपों को हटाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि संसद कानून में मौजूद असमानताओं को दूर करना चाहिए। यानी बात धूम—फिर कर संसद के दायरे में पहुंचती है। बहरहाल, हाई कोर्ट ने कहा— सदियों पुरानी सोच है कि पति अपनी पत्नियों के शासक होते हैं। वे उनके शरीर, उनके मन और आत्मा पर राज करते हैं। इस सोच को मिटा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मान्यता को बदलने की जरूरत है। उसने कहा महिलाओं के साथ अन्याय के मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के बढ़ते मामलों पर कहा कि पति की ओर से बीवी पर यौन हमले के गंभीर परिणाम होते हैं। इसका पत्नी पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

खतरनाक है, यह अल्पसंख्यकवाद

वेद प्रताप वैदिक

इधर सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी मजेदार याचिका पेश की गई है, अश्विनी उपाध्याय के द्वारा! उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि अल्पसंख्यकता के नाम पर कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ठगी चल रही है। जिन राज्यों में जो लोग बहुसंख्यक हैं, वे यह कहते हैं कि हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमें अल्पसंख्यकों की सब सुविधाएं अपने राज्य में भी मिलनी चाहिए। जैसे जम्मू-कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं लेकिन उन्हें इसके बावजूद वहाँ अल्पसंख्यकों की सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर के हिंदुओं, यहूदियों और बहाईयों को, जो वास्तव में वहाँ अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यकों की कोई सुविधा नहीं मिलती। यही हाल मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, लक्ष्मीपुर, मणिपुर और पंजाब का है।

इन राज्यों में रहनेवाले धार्मिक बहुसंख्यकों को भी अल्पसंख्यक मानकर सारी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। उपाध्याय ने अपनी याचिका में अदालत से मांग की है कि अल्पसंख्यकता का निर्णय राज्यों के स्तर पर भी होना चाहिए ताकि वहां के अल्पसंख्यकों को भी न्याय मिले। तर्क की दृष्टि से उपाध्याय बिल्कुल ठीक हैं लेकिन बेहतर तो यह हो कि देश में से मजहब, भाषा और जाति के आधार पर समूहों को बांटा न जाए। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद जरुरी है। दूसरे शब्दों में संख्या के आधार पर बना यह विशेष दर्जा राज्य स्तरों पर तो खत्म होना ही चाहिए, यह भी जरुरी है कि इसे अखिल भारतीय स्तर पर भी खत्म किया जाए।

1947 में भारत का बंटवारा इसी मजहबी संख्यावाद के कारण हुआ और अब देश के चुनाव और राजनीति का आधार यही जातीय संख्यावाद बन गया है। यही क्रम आगे चलता रहा तो 1947 में भारत के सिर्फ दो टुकड़े हुए थे लेकिन 2047 में भारत के सौ टुकड़े भी हो सकते हैं। यह बेहद खतरनाक प्रक्रिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने संविधान के ढीले-ढाले प्रावधानों का सहारा लेकर मजहबी और भाषाई आधार पर अपने नागरिकों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में बांट रखा है। हमारी केंद्र सरकार ने उक्त याचिका का समर्थन करते हुए संवैधानिक प्रावधान का हवाला भी दे दिया है। संविधान में ऐसा करने की छूट है। लेकिन किसी भी राष्ट्रवादी सरकार को हिम्मत करनी चाहिए कि वह इस राष्ट्रभंजक संवैधानिक प्रावधान को खत्म करवाए और देश के सभी नागरिकों को उनकी जरूरत के मुताबिक (जाति और धर्म के आधार पर नहीं) आवश्यक विशेष सुविधाएं अवश्य दी जाएं।

त्यागिक निर्णय के निहितार्थ

यालय की व्यवस्थाएं तब तक एक राय ही रहती हैं, जब तक विद्युत मुताबिक कानून निर्मित ना कर दे। इसका अपवाद सिर्फ तब होता फैसला संविधान के अनुच्छेद 140 को लागू करते हुए दिया हो। ध्यान में रखें, तो वैवाहिक बलात्कार के बारे में हाल में आए एक सीमित महत्व का निर्णय ही समझा जाएगा। वर्तमान सरकार

दायरे में पहुंचती है। बहरहाल, हाई कोर्ट ने कहा— सदियों पुरानी सोच है कि पति अपनी पत्नियों के शासक होते हैं। वे उनके शरीर, उनके मन और आत्मा पर राज करते हैं। इस सोच को मिटा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मान्यता को बदलने की जरूरत है। उसने कहा महिलाओं के साथ अन्याय के मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप के बढ़ते मामलों पर कहा कि पति की ओर से बीवी पर यौन हमले के गंभीर परिणाम होते हैं। इसका पत्नी पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

कब तक होगा जरारतों से समझौता

कुछ यही हाल अब भारत में भी हो रहा है। अभी ये नौबत नहीं आई कि तेल के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं या मारपीट हो रही है। मगर जिस तरह से महंगाई की चोट पड़ती जा रही है उसमें एक न एक दिन जनता टूट ही जाएगी। जो सत्ता में बैठे हैं, उनके घर, बंगले, रोज का आलीशान खर्च, सुरक्षा का तामझाम सब वैसे ही चलेगा, कटौती और समझौते केवल जनता को करने पड़ेंगे। देखना है कि जनता कब तक...

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दैनन्दिन कार्यों की एक सूची बताई है, जिसमें प्रमुख हैं— 1. पेट्रोल-डीजल-गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, 2. लोगों की श्खर्चे पे चर्चाए कैसे रुकवाऊं, 3. युवा को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं, 4. आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं 5. किसानों को और लाचार कैसे करूं। इस सूची को राहुल गांधी ने हैशटैग रोज सुबह की बात के साथ ट्वीट किया है। वे लगभग रोज ही किसी न किसी तरह बढ़ती महंगाई और लोगों की लाचारी को लेकर इसी तरह के ट्वीट करते हैं। उनके साथ—साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई अन्य नेता भी बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जतलाते हैं। कांग्रेस ने तो अब बाकायदा सङ्क पर उतरने का अभियान छेड़ दिया है। मगर सरकार महंगाई को लेकर मचे इस हंगामे की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार का घमंड तो देखिए वो इस मामले पर ऐसा कोई बयान भी नहीं देती जिससे लोगों को ये उम्मीद बंधे कि आज नहीं तो कल कीमतें कम होंगी या थोड़ी राहत मिलेगी। उल्टा भाजपा नेता ये दलील दे रहे हैं कि रुस और यूक्रेन के युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई है, मगर देश में पिछले नौ दिनों में आठ बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। दिखने को ये बढ़ोतरी कभी 70 पैसे, कभी 80 पैसे की होती है। लेकिन रोजाना की ये बढ़ोतरी एक महीने में आम आदमी की जेब पर कितनी भारी पड़ सकती है, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। चुनावी सम्भाओं में जनता के हमदर्द बनने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब महंगाई पर कोई आश्वासन देते नजर नहीं आते। खुद की गरीबी का अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोना रो चुके मोदीजी को अब गरीबों और मध्यमवर्गीय लोगों की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं दिखता। विभिन्न मंचों से वे अब भी बड़ी बातें करते ही नजर आते हैं। मुमकिन है कि भाजपा के राज में अगले कुछ सालों में भव्य राम मंदिर बनने के साथ हिंदुत्व का बोलबाला हो जाए। अल्पसंख्यक थोड़ा और डर कर रहने पर मजबूर कर दिए जाएं। धर्म की अफीम और राष्ट्रवाद के नशे में मोदी—मोदी के नारे लगाने वाले लोगों की गिनती कुछ और बढ़ जाए। विपक्षी दल आपसी एकता की बात करते—करते अंत में अपने—अपने स्वार्थों के दायरे में केंद्र रहें और भाजपा को अपनी मर्जी से देश को चलाने का मौका मिल जाए। लेकिन इस सबके बीच हिंदुस्तान का आम आदमी किस दशा में पहुंच चुका होगा, यह कल्पना करके ही डर लगता है। गरीबों को पांच किलो अनाज, किसानों को साल के कुछ हजार रुपए, और इसके साथ कभी एक—दो सिलेंडर, या थोड़ी बहुत कर्जमाफी के टुकड़े जनता के सामने डालकर उससे फिर से वफादारी की मांग की जाएगी। और रोजमर्झ के संघर्ष से टूट चुकी जनता शायद ऐसा करने

को तैयार भी हो जाए। आत्मसम्मान खो चुका देश किस तरह की गति प्राप्त होगा, यह समझना कठिन नहीं है। इन बातों में अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन फिलहाल हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और जिस तरह का हाल पड़ोसी देश श्रीलंका में हो चुका है, कोई आश्वर्य नहीं कि अगले कुछ वक्त में भारत के लोग भी ऐसे ही बदहाल दिखेंगे। श्रीलंका में भी राजपक्ष सरकार ने सत्ता संभालने के वक्त बहुत बड़े-बड़े दावे देशप्रेम, राष्ट्रवाद के नाम पर किए थे। अब उनका खोखलापन नजर आ रहा है। श्रीलंका के लोग बड़ती महंगाई के कारण अपने घरेलू खर्चों और रोजमर्ग के खानपान में भी कटौती कर रहे हैं। एक लीटर पेट्रोल की कीमत तीन महीने में दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। इस कीमत पर भी पेट्रोल व केरोसिन हासिल करने के लिए इतनी लंबी कतारें लग रही हैं कि श्रीलंका सरकार ने गैस स्टेशनों पर स्थिति को काबू में रखने के लिए सेना की टुकड़ियों को भेजा है। कतारों में लगे वृद्ध लोगों की जानें गई हैं और कुछ जगहों पर हिंसा भी हो गई है। कागज महंगा होने के कारण बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, कुछ अखबारों को अपना प्रिंट संस्करण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा है। देश विदेशी मुद्रा की भयंकर कमी से जूझ रहा है, जिस वजह से आयात करना असमंज होता जा रहा है। कर्ज का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण श्रीलंका की स्थिति डिफाल्टर जैसी हो रही है और अब वह चीन, भारत और आईएमएफ के सामने हाथ फैला रहा है। जब आप याचक की मुद्रा में होते हैं तो शोषण होना तय है। श्रीलंका के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर उसे कर्ज देने वाले अपने फायदे की शर्तें रखेंगे तो उसे मजबूरी में उन्हें मानना पड़ेगा। यह सब काम सरकार ही करेगी। लेकिन सरकार असल में अमूर्त होती है। उसमें सामने जो चेहरा होता है, वो सत्ता चलाता है, और उसके पास ये सुविधा होती है कि जब हालात संभालने कठिन हो जाए तो सत्ता से हट सकता है इससे उसके राजनैतिक जीवन पर असर पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक तौर पर वह उन दिक्कतों को नहीं छोलता, जो आगे जनता को सहनी होती हैं। सत्ता से हटा व्यक्ति लाचार हो सकता है, गरीब नहीं श्रीलंका में भी वहां की सरकार के लिए फैसलों का नतीजा जनता ही भुगतेगी। अगर कर्जदाता श्रीलंका का शोषण करने का मन बना लेंगे तो असल में शोषण जनता का ही होगा। कुछ यहीं हाल अब भारत में भी हो रहा है। अभी ये नौबत नहीं आई कि तेल के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं या मारपीट हो रही है मगर जिस तरह से महंगाई की चोट पड़ती जा रही है उसमें एक न एक दिन जनता टूट ही जाएगी। जो सत्ता में बैठे हैं, उनके घर बगले, रोज का आलीशान खर्च, सुरक्षा का तामझाम सब वैसे ही चलेगा, कटौती और समझौते केवल जनता को करने पड़ेंगे। देखना है कि जनता कब तक और किस हृद तक अपनी जरूरतों से समझौता करती है।

इस पर सभी पाटियों और राज्यों की सरकारों के साथ सहमति बनानी होगी। अभी जिस तरह से भारत में सारे चुनाव राष्ट्रपति मश्डल पर लड़े जा रहे हैं और गैर भाजपा दलों को हर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए तो उसका फायदा भी भाजपा को होगा। सो, कुल मिला कर अभी चुनाव सुधार के नाम पर जितने ...

અનુભૂતિ દિવોદી

अजात द्विवदा
भारत में लंबे समय से चुनाव सुधार की जरूरत बताई जा रही है। कुछ सुधार जरूर हो रहे हैं लेकिन वे इतने छोटे हैं कि उनका प्रत्यक्ष असर बहुत कम दिखाई देता है या फिर सुधार ऐसे हैं, जिनका कोई प्रभाव मतदान की प्रक्रिया पर नहीं हुआ है। जैसे जेएम लिंगदोह के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते यह प्रावधान किया गया था कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नामांकन पत्र के साथ एक हलफानामा देंगे, जिसमें उनकी संपत्ति, उनकी शिक्षा और उनके आपराधिक मामलों का ब्योरा होगा। माना गया था कि लोग प्रत्याशियों की आपराधिक छवि के बारे में जानेंगे तो उनको बोट नहीं देंगे। लेकिन हुआ इसका उलटा। पिछले दो दशक में आपराधिक रिकार्ड वाले सांसदों की संख्या में बहुत बढ़ातरी हो गई है। साथ की करोड़पति सांसदों—विधायकों की संख्या में भी रिकार्ड इजाफा हुआ है। तभी ऐसे प्रतीकात्मक चुनाव सुधार की जरूरत नहीं ॥

रहा है, जिससे लग रहा है कि मतदान का प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव होगा। यह कब होगा और कैसा होगा, यह नहीं कहा जा सकता है लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उठाए जा रहे कदमों और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयानों से इसे समझने की जरूरत है। इस लिहाज से दो बायान बहुत गौरतलब हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरा उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का है। दोनों ने नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। यह अपील बहुत आम है और दूसरी पार्टियों के नेता भी करते हैं, लेकिन वेंकैया नायडू ने एक कदम आगे बढ़ कर कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में 75 फीसदी मतदान होना चाहिए। ध्यान रहे पिछले चुनाव में 67 फीसदी से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ। सो, उप राष्ट्रपति ने पिछले चुनाव से आठ फीसदी ज्यादा और तीन—चौथाई मतदान की अपील की है।

यह संयोग है कि जिस समय उप

रहा है, जिससे लग रहा है कि मतदान की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव होगा। यह कब होगा और कैसा होगा, यह नहीं कहा जा सकता है लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उठाए यह रहे कदमों और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयानों से इसे समझने की जरूरत है। इस लिहाज से दो बयान बहुत गौरतलब हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरा उपराष्ट्रपति वैकैया नायडू का है। दोनों ने नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। यह अपील बहुत आम है और दूसरी पार्टियों के नेता भी करते हैं, लेकिन वैकैया नायडू ने एक कदम आगे बढ़ कर कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में 75 फीसदी मतदान होना चाहिए। ध्यान रहे पिछले चुनाव में 67 फीसदी से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ। सो, उपराष्ट्रपति ने पिछले चुनाव से आठ फीसदी ज्यादा और तीन-चौथाई मतदान की अपील की है।

यह संयोग है कि जिस समय उपराष्ट्रपति ने इसे किया है, वही समय जिसमें भाजपा ने अपनी विधायिका विजय की तरफ चली गयी। इसके बाद जिससे लग रहा है कि आपको यह चुनाव नहीं जीतना चाहिए, वही समय है जिसमें भाजपा ने अपनी विधायिका विजय की तरफ चली गयी। इसके बाद जिससे लग रहा है कि आपको यह चुनाव नहीं जीतना चाहिए, वही समय है जिसमें भाजपा ने अपनी विधायिका विजय की तरफ चली गयी।

ज्यादा मतदान करते हैं और उसके मुकाबले हिंदू मतदाता वोट डालने कम संख्या में निकलते हैं। अगर उनका मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो भाजपा को उसका फायदा हो सकता है। अनिवार्य मतदान या मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू ने कहा है कि सरकार प्रवासी भारतीयों को ऑनलाइन मतदान की सुविधा देने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा कदम होगा। ध्यान रहे अभी प्रवासी मतदाताओं को सेवा करते हैं।

से मतदान और घर बैठे मतद

बढ़ा रहा है। पहले सैनिकों और चुनाव प्रक्रिया में शामिल लोगों को ही पोस्टल बैलेट से मतदान की अनुमति थी। लेकिन अब बीमार और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी घर बैठे मतदान की सुविधा मिली है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ और समृद्ध जोड़े जा सकते हैं, जिनको घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी। कई विपक्षी पार्टियां इस व्यवस्था को लेकर आशंकित हैं और उनको लग रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ध्यान रहे स्वैच्छानिक संस्थाओं के कामकाज में जैसा पूर्वाग्रह हाल के दिनों में देखने को मिला है उसे देखते हुए किसी किसान के दमकाएँ की जांचकर्ता ऐसे दमकाएँ

The image is a full-page advertisement for 'Budh Prabandhan Aakash Printers'. At the top left is a golden statue of the Buddha. To its right is a large, stylized yellow 'बुद्ध' (Buddha) character. Below the character, the company name 'बुद्ध प्रबन्धन आकाश प्रिंटर्स' is written in large, bold, yellow and orange letters. Below the name are several examples of their printed products: a ledger book, a stack of colorful books, a brochure with a yellow arrow pointing to it, a newspaper clipping, a small booklet, a business card, and a large poster for 'लाल माता' (Lal Mata). At the bottom, there is descriptive text in Hindi and English, along with contact information: '8706051012 0453824450' and 'www.budhprabandhan.com'. The background features a blue gradient with decorative patterns.

श्री राम कथा के अष्टम दिवस ट्रेन के चपेट में आने से 70 वर्षीय महिला की मौत

राजा दशरथ द्वारा कैकई को दिए गए दो वरदान के बाबत कैकई का को भवन जाना

दैनिक बुद्ध का संदेश

रावट-संगंज / सोनभद्र।

वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर

स्थित मधुपुर बाजार के उत्तरी

छोर पर मानस प्रवक्ता साढ़ी

ऋग्वा शुक्ला रामलीला मैदान

में नव दिवसीय श्रीराम कथा में

अष्टम दिवस पर भगवान् श्री

राम के राज्याभिषेक की तैयारी

द्वारा राजाज्ञा जारी होते ही देवताओं के राजा

इंद्र के हवदय में खलबली मध्य

गई। भगवान् श्री राम का

राज्याभिषेक न हो, इसके लिए

इंद्र भगते हुए ब्रह्मा जी के पास

जाकर विनय करते हुए कहते हैं

कि प्रभु भगवान् श्री राम का

राज्याभिषेक हो जाएगा तो हम

लोगों का क्या होगा। इस पर

ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा तुम्हारा

विचार ठीक नहीं है। इस पर

इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु

दुष्ट दमन कार्य रुक जाएगा।

प्रभु श्री राम का दुष्ट दमन कार्य

हेतु ही अवतार हुआ है। इस पर

श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी

ब्रह्मा जी ने कहा कि तब तो

ठीक है, लोक कल्याण हेतु कुछ

भी किया जा सकता है। इसके

बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र से पूछा है-

क्या यह वह अवसर है कि आप वह

दोहराइए, इस पर राजा दशरथ

ने कैकई को सलाह दिया कि

श्री राम को राजगद्दी होते ही

माता कौशल्या का सम्मान बढ़

जाएगा। और आप दासी की

श्रेणी में आ जाएंगी। इन्हाँ सुनते

हैं। माता सरस्वती यदि मंथरा

के जिह्वा पर जाकर बौस कर

कल्याणकारी कार्य हेतु प्रेरित करें।

जिससे जनकल्याण हो सकता

है। इसके बाद माता सरस्वती ने

जन कल्याण हेतु कार्य प्रारंभ

कर दिया। जिसके तहत मंथरा

ने कैकई को सलाह दिया कि

श्री राम को राजगद्दी होते ही

माता कौशल्या की यह बात सुनते ही

कैकई तुरंत कोप भवन चली

जाती है। यह जानकारी होते ही

ही कैकई का विचार बदल जाता

है। कैकई ने कहा तब हमें क्या

राजा दशरथ कोप भवन जाकर

रानी को कोप भवन आने का

कारण पूछने पर कैकई ने कहा

ही राजा दशरथ मूर्छित होकर

कोप भवन में हमें दो वरदान देने

को कहे थे वह आज ही हमें दे

पड़े।

राज्याभिषेक हो जाएगा तो हम

लोगों का क्या होगा। इस पर

ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा तुम्हारा

विचार ठीक नहीं है। इस पर

इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु

दुष्ट दमन कार्य रुक जाएगा।

प्रभु श्री राम का दुष्ट दमन कार्य

हेतु ही अवतार हुआ है। इस पर

श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी

होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी

को याद दिलाया कि एक बार

राजा दशरथ देने तुरहें दो वरदान

देने को कहे थे वह पुनः

दोहराइए, इस पर राजा दशरथ

ने कैकई को बताया कि कैकई

कोप भवन चली जाएगा। और आप

दासी की यह बात सुनते ही

कैकई तुरंत बौस कर

कर दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी

को याद दिलाया कि एक बार

राजा दशरथ देने तुरहें दो वरदान

देने को कहे थे वह आज ही हमें दे

पड़े।

माता सरस्वती यदि मंथरा

के जिह्वा पर जाकर बौस कर

कल्याणकारी कार्य हेतु प्रेरित करें।

14 वर्ष का बनवास दे। इसके

बाद दासी मंथरा ने रानी कैकई

को याद दिलाया कि एक बार

राजा दशरथ देने तुरहें दो वरदान

देने को कहे थे वह पुनः

दोहराइए, इस पर राजा दशरथ

ने कैकई को सलाह दिया कि

श्री राम को राजगद्दी होते ही

माता कौशल्या का सम्मान बढ़

जाएगा। और आप दासी की

श्रेणी में आ जाएंगी। इन्हाँ सुनते

हैं। माता सरस्वती यदि मंथरा

के जिह्वा पर जाकर बौस कर

कल्याणकारी कार्य हेतु प्रेरित करें।

जिससे जनकल्याण हो सकता

है। इसके बाद माता सरस्वती ने

जन कल्याण हेतु कार्य प्रारंभ

कर दिया। जिसके बाद दासी

की याद दिलाया कि एक बार

राजा दशरथ देने तुरहें दो वरदान

देने को कहे थे वह आज ही हमें दे

पड़े।

दीजिए। इस पर राजा दशरथ

ने कहा कि यह कौन बड़ी बात

है, दो नहीं चार वरदान मांग

लो। इस पर रानी कैकई ने

फिर कहा नहीं हमें मात्र दो ही

वरदान देने को कहे थे वह पुनः

दोहराइए, इस पर राजा दशरथ

ने कैकई को सलाह दिया कि

श्री राम को राजगद्दी होते ही

माता कौशल्या का यह बात सुनते ही

कैकई तुरंत कोप भवन चली

जाती है। यह जानकारी होते ही

ही कैकई तुरंत कोप भवन चली

जाती है। यह जानकारी होते ही

राजा दशरथ कोप भवन जाकर

रानी को कोप भवन आने का

कारण पूछने पर कैकई ने कहा

ही राजा दशरथ मूर्छित होकर

कोप भवन में हमें धर्मतानी

पर आपने हमें दो धर्मतानी

पर आपने आपने हमें धर

